फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक पर नागरिक समाज का दृष्टिकोण

VANI
Celebrating 30 years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG
INDIA

फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक पर नागरिक समाज का दृष्टिकोण

लेखक : वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

मार्च 2019

कॉपीराइट © वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक की विषय वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से, प्रकाशक का आभार प्रकट करते हुए, पुनः प्रकाशित किया जा सकता है।

सहायताः हेनरिच बोल स्टिफटुंग

हिन्दी अनुवादः राजेन्द्र सिंह

प्रकाशकः
वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट, सैक्टर, द्वारका,
नई दिल्ली 110 077
फोनः 011–40391661, 40391663
टेलिफैक्सः 011–49148610
ईमेल : info@vaniindia.org
वेबसाइट :www.vaniindia.org

डिजाइन एवम प्रिंट :
ईमेल : artworkzdelhi@gmail.com

फाइनेंसिंग सस्टैनेबल डेवलपमेंट

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक पर नागरिक समाज का दृष्टिकोण

प्रस्तावना

विकासशील देशों में विकास अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुपक्षीय विकास बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्षों से ब्रैटन वूड्स सिस्टम वित्तपोषण पर विवरणात्मक नेतृत्व करने में अग्रणी रहा है और इसने ऐसी परियोजनाएं दी हैं जो तारीफ और आलोचना के योग्य हैं। एकध्रुवीय दुनिया के अपनी प्रासंगिकता खोने और वैश्विक उत्तर के पारंपरिक स्थानों पर कब्जा करने के लिए मध्य–आय वाले देशों के उदय के साथ वैश्विक दक्षिण के आदेश पर नई पहलों और प्रयासों के प्रारंभ होने से प्रक्षेप पथ में एक सुस्पष्ट बदलाव आया है। एआईआईबी एक ऐसी पहल है जिसने वित्तीय विश्व बुनियादी ढांचे के गलियारों और स्थायी लक्ष्यों की प्राप्ति में गति प्राप्त की है। इस बैंक की स्थापना साल 2015 में चीनी सरकार के संरक्षण में विकसित विश्व और एशिया में वित्तीय सतत् बुनयादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हुई थी। कई टिप्पणीकारों ने नोट किया है कि बैंक का उदय ब्रैटन वूडस और एशिया के अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे एशियाई विकास बैंक की संकीर्ण दूरदर्शिता का जवाब है। एआईआईबी 2030 के एजेंडे को हासिल करने के लिए जरूरी महत्वपूर्ण विकास लक्ष्यों को पूरा करने का एक माध्यम बनकर काम करने के बड़े एजेंडे पर खुद को स्थापित करता है। ग्रीन फाइनेंसिंग को सुविधाजनक बनाने, विकास के लिए न्यूनतम संरचनाओं के निर्माण और भ्रष्ट तरीकों के लिए कोई सहिष्णुता नहीं रखने के आधार पर, बैंक अपनी ग्रहणशीलता और परिवर्तनकारी शासन को चिन्हित करने के लिए संकेत के रूप में 'क्लीन, लीन और ग्रीन' की शपथ लेता है, जो मौजूदा बहुपक्षीय विकास बैंकों के अनुभवों पर निर्मित होगा। एआईआईबी स्पष्ट रूप से खुद को वैश्विक दक्षिण के बैंक के रूप में स्थापित करता है और स्थायी बुनियादी ढांचे की सफल इकाइयों के निर्माण के लिए वित्त को उत्प्रेरित करने के लिए अपनी भूमिका पर जोर देता है। वर्तमान अनुमानों से संकेत मिलता है कि दुनिया को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जिसका एहसास न होने पर गरीबी खत्म करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सरकारों के सामने वित्त संबंधी मुश्किल आएगी। अंतिम लाभार्थी तक वित्तपोषण नहीं पहुंचने से दक्षिण एशिया में स्थिति और भी चिंताजनक है, सिस्टम में अवलोकन किए जाने लायक कमियां हैं जिनके कारण वो पूरी तरह काम नहीं कर पाता।

किसी भी नागरिक समाज संगठन, भारत में स्वैच्छिक संगठनों के शीर्ष निकाय वॉलेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया द्वारा बैंक के कामकाज का विश्लेषण करने के इस पहले प्रयास में रूपरेखा, नीतियों को प्रासंगिक बनाने और बैंक के तौर–तरीकों को व्यापक रूप से समझने की कोशिश की है। ऐसे संस्थानों के साथ बातचीत में नागरिक समाज की भूमिका को

समझना महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। अनुसंधान भी नागरिक समाज के साथ सहयोग के लिए बैंक के विभिन्न संकेतकों और सकारात्मक परिणामों को बताने का प्रयास करता है। संस्थागत रोधन प्रभावकारी परिणाम नहीं देता है। इसके अतिरिक्त अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू नागरिक समाज को इस तरह के सम्मान की संस्थाओं को उत्तरदायित्व और पारदर्शिता मानकों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए संवेदनशील बनाना है। यह इस तथ्य के कारण जरूरी हो जाता है कि नागरिक समाज ने पारंपरिक रूप से उन निवेशों का समर्थन किया है जो सही, कुशल और प्रभावी हैं, लेकिन समान रूप से ऐसे तौर–तरीकों का विरोध किया है जो गोपनीयता के कारण संदेह में होते हैं या बुनियादी मानवाधिकारों पर समझौता करते हैं। एआईआईबी के साथ, भारत में पैर जमाने के लिए, बैंक के साथ बातचीत, परामर्श और परस्पर प्रभाव को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए नागरिक समाज को जुटाने की जरूरत होगी और जहां बैंक ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वहां विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक समाज मंचों को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा।

आखिर में मैं इस अध्ययन को पूरा करने के लिए हमें वित्तीय सहायता प्रदान करने में हेनरिक बोल स्टिफ्टंग के समर्थन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अध्ययन के प्रारूपण और लेखन के लिए अर्जुन फिलिप्स, प्रोग्राम मैनेजर, वानी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सादर

हर्ष जेटली
मुख्यकार्यकारी अधिकारी

अध्याय 1

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक का परिचय

बहुपक्षीय विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई), क्षेत्रीय और वैश्विक आकांक्षाओं के आर्थिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं और मांग संचालित अर्थव्यवस्थाओं को बनाने और रणनीतिक निवेश के माध्यम से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहक रहे हैं। यह महसूस किया गया कि विकास पर एक जनादेश के साथ विशेष वित्तीय संस्थान पूंजी निवेश के उद्देश्य को पूरा करेंगे और एक गुणक प्रभाव पैदा करेंगे। इसके परिणामस्वरूप वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मोनेटरी फंड का निर्माण हुआ, जिसे सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के रूप में जाना जाता है। इन वर्षों में, विकास बैंकों की श्रृंखला अस्तित्व में आई है लेकिन वैश्विक दक्षिण में पश्चिम के वर्चस्व और डॉलर के प्रभाव के कारण निराशा आई है जिसके चलते ब्रेटन वुड्स संस्थानों के निरंकुश व्यवहार की आलोचना होती है। विकास वित्त पोषण के मामले में मौजूदा संस्थान उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं जिसके कारण आर्थिक विचार से मोहभंग हो गया है।

एक बहस शुरू हुई कि विकास के वित्तपोषण के लिए सभी देशों में अत्यधिक गरीबी को दूर करने के लिए बड़े प्रसार की आवश्यकता है और वैश्विक स्तर पर बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए प्रति वर्ष कम से कम 5 ट्रिलियन डॉलर से 7 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में कहा गया कि वैश्विक दक्षिण में नए विकास बैंक स्थापित करने की आवश्यकता है जो विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और वित्तपोषण को प्राथमिकता देने में अधिक प्रभावी होंगे। एआईआईबी एक ऐसी संस्था है जो बहुपक्षीय विकास संगठनों की ताकत को बढ़ाएगी और एशिया–प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा निवेश; विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगी। बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों के लिए वित्त को सुरक्षित रखने का बैंक का उद्देश्य इसके सिद्धांत 'क्लीन, लीन, ग्रीन' में व्यक्त किया गया है। बैंक के दृष्टिकोण– स्थायी अवसंरचना, सीमा पार कनेक्टिविटी और निजी पूंजी संग्रहण पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए तीन

हस्तक्षेप विषयों की पहचान की गई है। बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है और जिन लिक्विन इसके अध्यक्ष हैं। इसकी अधिकृत पूंजी 100 अरब डॉलर है और कम से कम 84 देश इसके सदस्य हैं। बैंक ने अपनी कारोबार योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है, जो रणनीतिक फोकस, अपने कॉरपोरेट ब्रांड को आकार देने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने आदि पर जोर देती है।

चीन की उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने अंतरराष्ट्रीय वित्त और व्यापार में उसके वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया है। विनिर्माण क्षेत्र पर चीन के फोकस ने सरकार को एआईआईबी, ओबीओर और ब्रिक्स बैंक जैसी ढांचागत परियोजनाओं में निवेश करके उच्च क्षमता की समस्याओं का समाधान करने के लिए बाध्य किया है। चीन और विकासशील देश आईएमएफ और विश्व बैंक की शासन व्यवस्था के आलोचक रहे हैं। चीन की महत्वाकांक्षा है कि ब्रेटन वुड्स में अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए रेनमिन्बी ज़ोन बनाया जाए। टिप्पणीकारों ने पाया है कि एआईआईबी अपने क्षेत्रीय आधिपत्य को स्थापित करने और एशिया में अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र का मुकाबला करने की दिशा में चीन का एक प्रयास है। ओबीओआर को एक भू–राजनीतिक अभिव्यक्ति और कॉकेसस व पूर्वी यूरोप में नए संबंध बनाने के रूप में देखा जाता है और इसके रणनीतिक दृष्टिकोण ने भारत और वियतनाम जैसे देशों के साथ कई चिंताओं को जन्म दिया है। भारत को अतिक्रमण और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के आधार पर चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर आपत्ति है और इस कारण खासतौर पर वह ओबीओआर को लेकर प्रतिक्रिया पर उदासीन रहा है। चीन के साथ तनावपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारी होने पर भी इसने एआईआईबी में भारत के निवेश और बैंक के प्रशासन में भागीदारी को, एआईआईबी की गैर–पक्षपातपूर्णता को प्रोत्साहन देने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में उनकी रूचि न होने को बाधित नहीं किया है।

अध्याय 2

वैश्विक अवसंरचना ट्रैंड्स का परिदृश्य

बुनियादी ढांचा, निवेश परिवहन, आईसीटी, बिजली और बिजली के माध्यम से प्रदान की गई भौतिक और वास्तविक सेवाओं के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अगर क्षेत्र को अपनी वृद्धि को बनाए रखना है, गरीबी मिटानी है और मौसम परिवर्तन पर उत्तरदायित्व निभाना है तो वर्तमान में बुनियादी ढांचा निवेश में हर साल 1.0 ट्रिलियन डॉलर – 1.4 ट्रिलियन डॉलर की कमी का सामना करना पड़ता है। बढ़ती आय और बिजली, परिवहन और अन्य सेवाओं के लिए तेजी से शहरीकरण की मांग के साथ विनिर्माण, सेवाओं, व्यापार और मानव पूंजी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भौतिक बुनियादी ढांचा अत्यावश्यक है। सरकारें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास पर जोर दे रही हैं और पूंजी की मान्यता और विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और सार्वजनिक–निजी भागीदारी में बहुत रूचि है।

क) एक समर्थवान के रूप में बुनियादी ढांचा निवेश

अवसंरचना निवेश उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक के तौर पर काम करता है और नागरिकों के जीवन और विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की संभावना पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकता है। आर्थिक समृद्धि और गरीबी उन्मूलन में अवसंरचना निवेश एक प्रमुख चालक है. यह इसे हमारे दीर्घकालिक अनुमानों का एक महत्वपूर्ण पहलू है और सरकार द्वारा व्यापक रूप से लोकलुभावन आंदोलन के प्रहाव को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यहां तक कि परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में भी, नए और उन्नत बुनियादी ढांचे का निर्माण आर्थिक विकास को बनाए रखने और समग्र विकास प्रतिमानों के निर्माण के लिए अनिवार्य है।

ख) अवसंरचना निवेश के लिए मौजूदा ट्रेड्स

आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष 1.25 ट्रिलियन डॉलर–1.5 ट्रलियन डॉलर तक निवेश की आवश्यकता होती है। ताकि अनचाहे आर्थिक उभार को सुव्यवस्थित किया जा सके, शहरीकरण के दबावों का जवाब दिया जा सके, विकास

लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और पर्यावरणीय जोखिमों को कम किया जा सके। सरकारों द्वारा अवसंरचना निवेश वर्तमान में वैश्विक जीडीपी के लगभग 4 प्रतिशत के समान अवसंरचना निवेश में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर या 27 प्रतिशत की कमी हुई है। इसलिए अवसंरचना लक्ष्यों को प्राप्त करने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए समावेशी वित्तीय आर्किटेक्चर बहुत महत्वपूर्ण हैं।

ग) बुनियादी ढांचे के उपभोग के लिए भविष्य में संरचना

2040 तक वैश्विक अवसंरचना निवेश की जरूरतों के लिए एशिया 54 प्रतिशत और अमरीका, भारत और जापान आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार होगा। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश की मांग अवसंरचना के कारण है और विकासशील देशों में ये मांग शहरीकरण के कारण उच्च विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन के कारण है। सामाजिक आवश्यकताओं के संबंध में, सभी देशों में गरीबी को मिटाने के लिए वैश्विक सुरक्षा जाल की अनुमानित लागत लगभग 66 अरब डॉलर सालाना है। वैश्विक दक्षिण, वैश्विक अवसंरचना निवेश का लगभग दो–तिहाई हिस्सा होगा। यह आवश्यकता पुरानी अक्षम और प्रदूषणकारी प्रणालियों से आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर प्रदान करती है।

घ) अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती

अवसंरचना की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में चार प्राथमिक चुनौतियां हैंः

- सरकार ने राजकोषीय चुनौतियों का सामना किया है और इसलिए निवेश में कटौती कर रही है;
- निजी निवेशक दीर्घकालिक, जोखिमपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी लगाने में अनिच्छुक हैं;
- सरकारों के लिए अल्पकालिक अभियानों में दीर्घकालिक आवश्यकताओं के बीच व्यापार–बंद को संतुलित करने की चुनौती;
- राष्ट्रीय सरकारों को ऐसे आर्थिक सुधारों के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए।

अध्याय 3

एआईआईबी का संस्थागत आर्किटेक्चर

एआईआईबी की उत्पत्ति 'क्लीन' शासन के आधार पर हुई, जिसका मतलब है कि बैंक अपने से जुड़े संस्थानों के सकारात्मक पहलुओं पर निर्माण करेगा और ब्रेटन वुड्स के संस्थानों पर कब्जा करने वाली नौकरशाही उलझनों से बचेगा। विश्व बैंक के लिए सुधार–बैंकों की शासन संरचनाओं के निर्माण के लिए अभिन्न अंग बन गए हैं और एआईआईबी को बनाते समय सरकार द्वारा 'अच्छे शासन' के उदाहरणों को दोहराने के लिए इनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया था। एआईआईबी का शासन अन्य एमडीबीज़ के साथ एक त्रिस्तरीय स्तर के आर्किटेक्चर से युक्त है, जिसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अध्यक्ष शामिल हैं।

क) एआईआईबी की स्थापना संरचना

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास बैंक के समग्र अधिकार हैं और उसके लिए एक वार्षिक बैठक आयोजित करना अनिवार्य है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बुलाया जाता है। बैंक के परिचालन को इसके समझौते के लेखों में अच्छी तरह व्यक्त किया गया है। एमडीबी और एआईआईबी के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि एआईआईबी में अनिवासी बोर्ड निदेशक होते हैं। एआईआईबी की मतदान शक्ति देश की कुल पूंजी सदस्यता के साथ जुड़ी होती है। इससे सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाले देश के पास सबसे बड़ी मतदान शक्ति होती है।

ख) सदस्यता

एआईआईबी में सदस्यता को क्षेत्रीय और गैर–क्षेत्रीय सदस्यों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें ताइवान और उत्तर कोरिया एक अपवाद हैं। क्षेत्रीय सदस्य वे हैं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशिया और ओशिनिया के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में स्थित हैं।

एआईआईबी गैर–संप्रभु संस्थाओं को एआईआईबी सदस्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है और इसके 57 संस्थापक सदस्य हैं। एडीबी के आधे से अधिक सदस्य एआईआईबी में शामिल हो गए हैं और 2017 में लगभग 25 अतिरिक्त देशों के शामिल होने की संभावना है।

ग) मतदान अधिकार

एआईआईबी में मतदान प्रत्येक सदस्य को समान मत की बजाय एमडीबी के मतदान के अनुरूप है। प्रत्येक एआईआईबी सदस्य की कुल मतदान शक्ति में उसके शेयर वोटों का योग होता है, जो किसी सदस्य के पास मौजूद स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट के बराबर होता है। मूल वोट– प्रत्येक सदस्य के लिए एक समान है और यह एमडीबी में एक सामान्य सुविधा है लेकिन सार्वभौमिक नहीं है। संस्थापक सदस्य वोट– प्रति सदस्य 600 वोटों पर निर्धारित होता है। संस्थापक सदस्य के वोट उन हस्ताक्षरकर्ता को सौंपे जाते हैं जो एआईआईबी चार्टर में निर्धारित समय सीमा से पहले सदस्यता की आवश्यकताओं को पूरा करके संस्थापक सदस्य बन जाते हैं।

घ) परिचालन नीति

17 जनवरी को वित्त पोषण पर बोर्ड द्वारा अपनाई गई परिचालन नीति बैंक की वित्तपोषण नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित करता है जो एक विशेष परियोजना में निवेश के लिए एआईआईबी के लिए संतोषजनक होना चाहिए, जैसे कि परिभाषित विकास उद्देश्य, उत्पादक गतिविधियां, वित्त के वैकल्पिक स्रोत और अन्य एआईआईबी नीतियों की अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना।

अध्याय 4

एआईआईबी के पर्यावरणीय और सामाजिक ढांचे का आंकलन

एआईआईबी पर्यावरणीय और सामाजिक ढांचे को एक प्रणाली के रूप में लागू करता है जो पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से स्थायी विकास परिणामों को प्राप्त करने में बैंक और उसके ग्राहकों की मदद करता है। यह पर्यावरणीय और सामाजिक नियोजन और जोखिमों के प्रबंधन में अच्छे अंतरराष्ट्रीय तरीकों का एकीकरण करने और बैंक समर्थित परियोजनाओं पर निर्णय लेने और तैयारी व कार्यान्वयन में प्रभावों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। एआईआईबी ने अपने पर्यावरणीय और सामाजिक ढांचे को विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे मौजूदा डीआईएफ के अनुभवों के आधार पर विकसित किया है। जिसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अध्यक्ष शामिल हैं।

क) ईएसएफ की मुख्य विशेषताएं

एसडीजीस की ओर काम करना	विकास के लिए समावेशी नीतियां	सहभागी निर्णय के लिए जगह
बैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आयामों (आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय) और सिद्धांतों (परियोजनाओं की पहचान, तैयारी और कार्यान्वयन) को संबोधित करने की आवश्यकता को पहचानता है।	एआईआईबी विकास को प्राप्त करने के लिए सामाजिक विकास और अनिवार्य संकतेकों को शामिल करने पर विचार करता है; जिसके परिणामस्वरूप लोगों को विकास में भागीदारी देने और विकास से लाभान्वित होने का अधिकार है।	हितधारकों के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के आकलन और प्रभावों के लिए महत्वपूर्ण है।

परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्यवन और निगरानी	बहु–हितधारक संबंध	लैंगिक समानता को संतुलित करना और प्रोत्साहन देना
सक्रिय क्षेत्र–आधारित पर्यवेक्षण, निगरानी और सत्यापन, कार्यान्वयन समर्थन और संस्थागत मजबूती के माध्यम से, एआईआईबी परियोजनाओं के लिए क्लाइंट–साइड परिपालन का समर्थन करती है।	परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ समवर्ती बनाने के लिए बहु–हितधारक परामर्श आवश्यक हैं। बैंक परियोजनाओं की समयावधि में परामर्श पर जोर देता है और समावेश, पहुंच व पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करता है।	बैंक क्लाइंट्स को अवसर की समानता और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए समावेशी और लैंगिक–उत्तरदायी तरीके से अपनी परियोजनाओं के डिजाइन को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ख) पर्यावरणीय और सामाजिक ढांचे की रूपरेखा

एआईआईबी के पर्यावरणीय और सामाजिक ढांचे में मुख्य रूप से दो स्तंभ शामिल हैं–

1. पर्यावरणीय और सामाजिक नीतिः इसमें प्रत्येक परियोजना के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताएं शामिल हैं।
2. पर्यावरणीय और सामाजिक मानक संकेतकों सहित अनिवार्य आवश्यकताएं हैंः– पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन व प्रबंधन; अनैच्छिक पुनर्वास; स्थानीय लोग

ग) उचित परिश्रम और जोखिम आंकलन

एआईआईबी वर्गीकरण प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना के जोखिमों को निर्धारित करता है। परियोजना क्षेत्र में उच्चतम पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिम का निर्धारण करने में वर्गीकरण का अनुसरण किया जाता है। बैंक पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की परिष्कृत समझ प्रदान करने के लिए परियोजना की क्षेत्र–आधारित समीक्षा कर सकता है और इन जोखिमों व प्रभावों के मूल्यांकन के लिए क्लाइंट्स की साइट के आधार पर तैयारी का समर्थन कर सकता है।

घ) पर्यावरणीय और सामाजिक आंकलन

शुरुआत में क्लाइंट्स को परियोजना के परिपालन में आने वाले पर्यावरणीय

और सामाजिक जोखिमों पर आकलन प्रक्रिया तैयार करने की जरूरत होती है। हालांकि, कुछ देशों में कानून और प्रक्रियाओं को अलग–अलग पर्यावरणीय व सामाजिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में बैंक ग्राहकों द्वारा तैयार किए गए प्रलेखन की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम के मूल्यांकन और प्रभावों के साथ–साथ अल्पीकरण और निगरानी के प्रावधान भी प्रदान करता है।

ड.) पर्यावरणीय और सामाजिक ढांचे में संरचनात्मक अंतर पर काम करना

1) बैंक के पर्यावरणीय और सामाजिक ढांचे के खिलाफ कई तर्क दिए गए हैं जो बैंक के आर्किटेक्चर की आलोचना करते हैं। एआईआईबी को अपने पर्यावरणीय और सामाजिक ढांचे के कार्यान्वयन में इन तीन प्राथमिक संरचनात्मक कमियों पर काम करना चाहिए। इनमें शामिल हैंः–

   अ) स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श का दायरा बढ़ाने और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार निःशुल्क, पूर्वगामी, सूचित सहमति का पालन करने की जरूरत है।

   ब) बैंक और देश के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों को एकीकृत करने के लिए एक रूपरेखा बनाने की जरूरत है।

   स) ऊर्जा रणनीति में शामिल थर्मल आधारित टेक्नोलॉजीज का उपयोग कम करें और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजीज की ओर बढ़ें।

अध्याय 5

एआईआईबी की विषयगत प्राथमिकताएं

रणनीतिक एकीकरण और प्रोग्रामिंग

एआईआईबी ने एक एशिया स्तर के वित्तीय संस्थान की अवधारणा को पूरा करने के लिए एक व्यापक उद्देश्य को रेखांकित किया है जो पूरी तरह से अवसंरचना के निर्माण के संसाधन उत्पादन पर ध्यान देगा। बैंक ने माना है कि ग्राहक पक्ष अपनी विषयगत गतिविधियों को प्रगतिशील रूप से आकार देने की मांग करता है जो कि मूल रूप से बैंक के उद्देश्य और मिशन से जुड़े होते हैं। ये हैंः सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश; सीमा पार देशों से जुड़ाव; निजी पूंजी जुटाना। इसके अतिरिक्त बैंक एक ऐसी सेक्टर रणनीति तैयार करने पर जोर देता है जो ऊर्जा के अवसंरचना को लक्षित करती है और रणनीति को लागू करने के लिए, बैंक अपने सदस्यों को पेरिस समझौते में व्यक्त की गई उनकी भूमिका के लिए समर्थन देगा।

क) सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना

विकासशील दुनिया में तेजी से आर्थिक परिवर्तन के लिए सुव्यवस्थित अवसंरचना निवेश के माध्यम से लाखों लोगों गरीबी से निकालने में सफलता मिली है। हालांकि, विकास में तेजी आने के साथ मौसम–परिवर्तन, जल प्रदूषण और बढ़ते शहरीकरण स्वरूप के कारण पर्यावरण में गिरावट आई है। इन समस्याओं में अब तक हासिल हुई वृद्धि और भविष्य के अनुमानों में रुकावट डालने की क्षमता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपने रणनीतिक नज़रिए को तेज करना होगा और 'डू नो हार्म' की नीति के सिद्धांत का पालन करना होगा। यह इस संदर्भ में है कि एआईआईबी ने स्थायी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को एकीकृत करने के लिए जोर देना अनिवार्य कर दिया है।

ख) सीमा पार कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास की सुविधा के लिए रीढ का काम करती है। बहुत कम एशियाई देश हैं जिन्होंने विश्वस्तरीय और सक्षम परिवहन प्रणाली बनाने के लिए साधन और शक्ति विकसित की है। लेकिन, फिर भी उच्च लागत के कारण बाहरी बाजारों तक पहुंचने के संदर्भ में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप ये परिवहन प्रणालियां नकारात्मक प्रभावों के फैलने के लिए जिम्मेदार हैं। विकास के नए संचालकों से क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास के भविष्य के स्वरूपों को आकार देने की उम्मीद है, क्योंकि देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में आने वाली गिरावट के साथ संतुलन बनाने के लिए क्षेत्रीय बाजारों की ओर देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्तमान में एक महत्वपूर्ण असंतुलन के दौर से गुजरने के साथ दुनिया अब वैश्विक विकास और अधिक कुशल परिवहन प्रणालियों को बनाए रखने के लिए एशिया की ओर देख रही है।

ख) निजी अर्थव्यवस्था जुटाना

दुनिया भर में अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए मौजूदा जरूरतों में बहुत बड़ा अंतर है और 2030 तक एसडीजी प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक अवसंरचना पर वैश्विक वार्षिक खर्च में 2015–2030 के दौरान 1.6 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। उभरते हुए बाजारों और विकासशील देशों में अधिकांश निवेश की आवश्यकता होगी और अवसंरचना की मांग का सबसे बड़ा हिस्सा एशिया में है। यह ध्यान दिया जाता है कि 1990 के बाद से आधारभूत संरचना में निजी भागीदारी (पीपीआई) औसतन 13 प्रतिशत प्रति वर्ष की गति से बढ़ी है। अब निजी क्षेत्र विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के 20–25 प्रतिशत की आपूर्ति करता है, इसलिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सरकारें अवसरंचना के निवेश के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए दिलचस्पी ले रही हैं।

अध्याय 6

भारत और एआईआईबी

भारत ने अप्रैल 2015 में एआईआईबी में शामिल होने का फैसला किया और इसने बैंक में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरहोल्डर बना। जून 2018 में, भारत ने मुंबई में एआईआईबी की दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। मुंबई में एनुअल जनरल मीटिंग में एआईआईबी ने भारत में अवसंरचना उपयोगिताओं को डेवलप करने की दिशा में कई प्रकार के निवेश की घोषणा की। इनमें निम्नलिखित शामिल थे–

1) राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश निधि के लिए $ 200 मिलियन का प्रावधान करना (स्वीकृत)
2) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना– III को विकसित करने की दिशा में $475 मिलियन
3) आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना
4) आंध्र प्रदेश शहरी जल आपूर्ति एवं रिसाव प्रबंधन सुधार परियोजना
5) अमरावती दीर्घस्थायी राजधानी शहर विकास परियोजना
6) मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना (स्वीकृत)
7) गुजरात ग्रामीण सड़क (स्वीकृत)
8) आंध्र प्रदेश 24x&– सभी के लिए बिजली (स्वीकृत)
9) ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजना (स्वीकृत)
10) मर्गन स्टेनली इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (स्वीकृत)

भारत सरकार द्वारा मांगी गई कुल निवेश–राशि $2 बिलियन है, जबकि छह परियोजनाओं के लिए वास्तविक रूप में स्वीकृत निवेश–राशि $1.2 बिलियन है तथा $1.9 बिलियन के लिए अनुमोदन अनिर्णीत है।

भारत में एआईआईबी की परियोजनाओं का आकलन करना

आंध्र प्रदेश 24x&– सभी के लिए बिजली

इसका उद्देश्य ग्राहकों को बिजली पहुंचाने के लिए प्रणाली की क्षमता को बढ़ाना, और आंध्र प्रदेश राज्य में चयनित क्षेत्रों में बिजली के वितरण में परिचालन दक्षता एवं प्रणालीगत विश्वसनीयता में सुधार लाना था। परियोजना का लक्ष्य आंध्र प्रदेश राज्य में सभी के लिए 24x7 बिजली योजना के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करना है।

मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्क (कनेक्टिविटी) परियोजना

इसका उद्देश्य मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों के सुगम्यता में सुधार लाने, और मौसम परिवर्तन के प्रति समुत्थान–शक्ति को बढ़ाने के साथ–साथ अपने ग्रामीण सड़क नेटवर्क और सड़क सुरक्षा की देखरेख करने में राज्य की क्षमता का निर्माण करना था।

अध्याय 7

सस्टेनेबल वित्त–पोषण के लिए कमियों को दूर करना

एआईआईबी को मांग की पूर्ति करने और एशिया एवं विकासशील दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के अपने मिशन और विजन को हासिल करने के लिए यूएस $26 ट्रिलियन का निवेश करना होगा। बैंक के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षा होगी – परियोजनाओं के गुणात्मक पहलुओं का निराकरण करना, बड़े लक्षित समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और कोई भी प्रतिकूल स्पिलओवर प्रभाव न हो, यह सुनिश्चित करना।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना संधारणीयता का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो स्थानीय संदर्भ पर निर्भर करता है और अल्पकालिक सुधार लंबी अवधि में एक स्थायी समाधान नहीं हो सकते हैं। वैश्विक सस्टेनेबल अवसंरचनात्मक अंतर को पाटने की कुंजी नवीकरणीय–ऊर्जा निवेश है और इस लक्ष्य का समर्थन करने के लिए बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, राष्ट्रीय विकास बैंकों और अन्य विकास वित्तीय संस्थानों को इस बात की सलाह दी गई है कि वे सस्टेनेबल अवसरंचना में अपने निवेश को दोगुना करें। जब सरकारें अपनी अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए सक्षम और इच्छुक हों, तो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, अससंरचना के अंतर को कम करने का अवसर प्रदान करता है।

क) गुणक (मल्टीप्लायर) होने में सस्टेनेबल अवसंरचना का तत्व

उपयोगिताओं का निर्माण करने में सस्टेनेबल अवसंरचना के गुणक प्रभाव को सह–हितलाभों के रूप में निरूपित किया जा सकता है, इसमें शासन, मौसम परिवर्तन प्रशमन एवं अनुकूलन लक्ष्यों को हासिल करना शामिल है। ये अपने पूरे जीवनकाल में सस्टेनेबल अवसंरचनात्मक (सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण) परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक परियोजना के व्यापक अधिदेश के संदर्भ में परियोजना की व्यवहार्यता और संभवता का आकलन करने के लिए मापनीय लक्ष्यों के रूप में सूचकों का उपयोग किया जा सकता है।

ख) अवसंरचनात्मक निवेशों में मानवाधिकार फ्रेमवर्क को मुख्य धारा में लाना

मानव अधिकार अवसंरचनात्मक निवेशों के समग्र ढांचे में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है और इस प्रतिमान को बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) के कार्यनीतिक दस्तावेजों के भीतर एकीकृत करने में टाल–मटोल किया जाता है। जबकि अवसंरचना के लिए पर्याप्त औचित्य रहे हैं, फिर भी ऐसे उदाहरणों की कमी रही है जिनमें 'आर्थिक गलियारों' के निर्माण के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक विस्थापन हुआ हो। परियोजना के डिजाइन, प्रचालन चरण और कार्यान्वयन में मानवीय त्रुटि की संभावना से बड़े पैमाने पर ऐसे मानवाधिकार उल्लंघन हो सकते हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षित किया गया है।

ग) प्रभावी और नवीनीकृत सुरक्षित तंत्र

बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा ऑडिटिंग मैकेनिज्म और सुरक्षण कार्यकरण में पेशेवर नहीं रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के हितों की समीक्षा नहीं हो पाती है। संकल्पनात्मक संरचनाओं और व्यावहारिक बाधाओं का निराकरण किए जाने और बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) द्वारा देशगत प्रणालियों का उपयोग किए जाने की जरूरत है। इसलिए, एआईआईबी के लिए यह अनिवार्य बन जाता है कि यह पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा रक्षोपायों की एक ऐसी लचीली और नवोन्मेषी संरचना को अपनाए जो विकासशील देशों के विधानों के साथ अतिव्याप्त नहीं करे और उनके घरेलू कानूनों के आश्रय में समुदायों और लाभार्थियों की रक्षा करने का काम करे।

घ) बहु–हितधारक सहभागिता के लिए सिविल सोसायटी फ़ोरम संस्थापित करना

बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को अपनी नीतियों, रूपरेखाओं के प्रति जवाबदेह बनाने में सिविल सोसायटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विभिन्न सामाजिक ऑडिटिंग टूल्स के उपयोग के माध्यम से निवेशों पर महत्वपूर्ण आकलन उपलब्ध कराती है। यूएन, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन जैसे बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) सिविल सोसायटी की भागीदारी के लिए संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करते हैं, जबकि एआईआईबी में सिविल सोसायटी की भागीदारी के लिए कोई संरचना नहीं है, फिर भी बैंक के स्टाफ के साथ बातचीत करने के लिए गैर–सरकारी समूहों को एक स्थान दिया गया है। जून 2018 में, पूरे भारत के सिविल सोसायटी संगठनों को इंटरफ़ेस के लिए और इसकी विभिन्न गतिविधियों और रूपरेखाओं पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसलिए सिविल सोसायटी भागीदारी अपने निवेश पोर्टफोलियो का लाभ उठाने के लिए बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगी और परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान अपने पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकनों में सहयोग प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर आंकड़े एकत्रित करने का स्रोत बनेगी।

अध्याय 8

निष्कर्ष

एआईआईबी के पास एशियाई क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का वित्तपोषण करने का एक दुर्वह कार्य है। एशिया क्षेत्र उन महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के अपने प्रयास के पहले महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करेगा, जो अधिकांशतया आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में कार्यनीतिक निवेश के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। अपने निवेशों के समग्र कवरेज का सम्पूर्ण करने के लिए बैंक द्वारा समाविष्ट की गई सांस्थानिक नीतियां और रूपरेखाएं उल्लेखनीय हैं और वर्ल्ड बैंक एवं इंटरनेशनल मोनेटरी फंड जैसे अन्य बहुपक्षीय बैंकों के अनुभवों पर कार्य करती हैं। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बैंक चीन के बढ़ते भू–राजनीतिक महत्व के प्रति कितना सुसंगत होकर काम करता है।

यह रिपोर्ट बैंक द्वारा अपनाए गए उन प्रमुख विषयगत क्षेत्रों और भूमिका के बारे में विस्तार से बताती है, जो एआईआईबी द्वारा अपने विजन की दिशा में जाती है। पीपीपी और पीपीआई जैसे नवोन्मेषी तंत्रों के माध्यम से संसाधनों को उत्प्रेरित करने और उनका दोहन करने की जरूरत बैंक के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इसी तरह, बैंक को ग्रीन फाईनेंसिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने और निम्न कार्बन–अर्थव्यवस्थाओं के लिए जरूरी परिवर्तनकाल सुलभ कराने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक को एक ऐसी कार्यनीति के साथ सफल होना होगा जो नवीकरणीय ऊर्जा में कार्यनीतिक निवेश प्रदान करे। संपूर्ण क्षेत्रों में क्र०स–कनेक्टिविटी के संदर्भ में, बैंक को ऐसी अवसंरचना में निवेश करने के प्रति सावधान रहना होगा जो अनिवार्य मानवाधिकारों की परिकल्पना नहीं करे और जवाबदेही के ऐसे उचित तंत्रों की स्थापना नहीं करे जो स्थानीय समुदायों और लाभार्थियों की चिंताओं का जायजा लेने के लिए बनाए जाते हैं। वर्तमान में बैंक ने ऐसी परियोजनाएं शुरू की हैं जिन्हें अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों के

साथ मिश्रित वित्त पोषण का सहारा मिला हुआ है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एआईआईबी एकल परियोजनाओं और निवेशों पर कैसा निष्पादन करता है। रिपोर्ट में निदर्शित किया गया है कि दीर्घस्थायी विकास के वित्तपोषण के अनिवार्य आधारभूत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सिविल सोसायटी, व्यथित पक्षकारों और समूहों के साथ ऐसे सहभागी विमर्शों को मुख्यधारा में लाना अनिवार्य हो जाता है जो बैंक के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकें। इसके अलावा, बैंक के लिए अपने ईएसएफ पर आधारित मूल्यांकन और संकेतकों का अध्ययन करने के लिए अपने ग्राहकोनुकूलित साधनों को विकसित करना काफी अधिक उत्पादक होगा।

यह जरूरी है कि बैंक अपने निवेशों में जेंडर पॉलिसी के दायरे का विस्तार करे। यह नोट किया जाता है कि बैंक ने हाल ही में अपनी निवेश परियोजनाएं शुरू की हैं और इसलिए प्रभावों और परियोजना–उपरांत प्रेक्षणों का उपलब्ध न होना, निष्पादित गुणात्मक एवं मात्रात्मक सकारात्मक परिणामों का आकलन करने के कार्य को मुश्किल बनाती है। भविष्य के सिविल सोसायटी आकलन के लिए, बैंक के सामने आए प्रभावों और चुनौतियों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान में, बैंक के पास परियोजनाओं की जो पाइपलाइन है, वे 2022 में पूरी की जानी हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंक का लक्ष्य एशिया क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करना है और इसे भारत समेत अनेक देशों से अनुक्रियाशील प्रतिक्रिया मिली। भारत ने 2 बिलियन यूएस डालर के वित्तपोषण की मांग की है। जैसे–जैसे अधिक से अधिक देश बैंक में शामिल होते हैं, बैंक का भौगोलिक विविधीकरण क्षेत्र में कार्यनीतिक निवेश की पूर्णता बनाए रखने और विकासात्मक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- भारत में नागरिक समाज संगठनों के संदर्भ में स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- फाइनेंशिंग सस्टेनेएबल डेवलपमेंट सिविल सोसाइटी परस्सपैक्टिव ऑन एशियन इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (अंग्रेजी)
- स्टडी ऑन कैपासिटी बिल्डिंग एंड नीड ऐसैसमेंट ऑफ वालंटरी ऑग्रेनाइजेशनस (अंग्रेजी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाने की दिशा में: एक अध्ययन रिपोर्ट
- इंडिया–अफ्रीका पार्टनरशिपः ए सिविल सोसाइटी परस्पैक्टिब (अंग्रेजी)
- उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एसएससी में विकास वित्त और सहयोग (अंग्रेजी और हिन्दी)
- इन्कम टैक्स एक्ट फार दी वालंटरी सैक्टर – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- मॉडल पॉलिसी रजिस्ट्रेशन – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राइमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह
- भारत की विकास सहयाताः रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ
- जी 20 में भारत की भूमिकाः एक नागरिक समाज दृष्टिकोण
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राइमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)

VANI
Celebrating 30 years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट,
सैक्टर–8, द्वारका, नई दिल्ली 110 077

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

हेनरिच बोल स्टिफटुंग (एचबीएफ)
सी–20, कुतुब इंस्टीच्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली 110 016